

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :- 11/2018

निर्णय दिनांक :- 31.03.2021

प्रार्थी :-

दाकू पुत्री स्व.वनारामजी (पत्नि बालाराम), आयु-41 वर्ष जाति- जणवा चौधरी,
निवासी - नारलाई, तहसील- देसूरी जिला-पाली(राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. चेलाराम पुत्र स्व. वनाराम, आयु- वयस्क
2. पुनाराम पुत्र स्व. वनाराम, आयु-वयस्क
3. नोजकी पत्नि स्व. दौलाराम, आयु -वयस्क
4. विक्रम पुत्र स्व. दौलाराम, आयु -वयस्क
5. अशोक पुत्र स्व. दौलाराम, आयु -अवयस्क
6. प्यारी पुत्री स्व. दौलाराम, आयु-अवयस्क
7. फउडी पुत्री स्व. दौलाराम, आयु-अवयस्क,
जातिगण-जणवा चौधरी, निवासीगण -नारलाई, तहसील देसूरी, जिला-पाली (राज.)
अप्रार्थी सं.- 4 से 7 अवयस्क जरिये कुदरती वलीया माता अप्रार्थी सं. - 3 के
8. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

(वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

-:प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :-

उपस्थिति:-

1. श्री मुकेश कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुरेश दवे अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :-31.03.2021

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि-प्रार्थियों की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गांव-नारलाई, पटवार क्षेत्र- नारलाई, तहसील-रानी, जिला-पाली (राज.) में संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजियात खसरा नम्बर 2325, 2326, 2328, 2329, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2366 कुल खसरा- 22 कुल

पेज नम्बर 2 पर लगे तार.....



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज नम्बर 2 राजस्व विधि नम्बर 11/2016 अनवान वामु ब्राम चेलाराम व अन्य अनवगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देगुरी

क्षेत्रफल - 59.3800 हैक्टर, कुल लगान रूपयां- 1133.38 एवं खसरा नम्बर- 1449, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, कुल खसरा-14 कुल क्षेत्रफल-11.8100 हैक्टर, कुल लगान रूपयां - 281.12 विद्यमान है।


उपरोक्त वर्णित खसरान की आराजियात में प्रार्थिनी के पिता श्री वनाराम पुत्र भगारामजी की खातेदारी आधिपत्य का कब्जा काश्त सुदा संयुक्त हिस्सा विद्यमान था, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 व मृत दौलाराम द्वारा विरासत नामान्तरकरण के जरिये सिर्फ इन्हे ही मृत वनाराम के वारिस उत्तराधिकारी बता कर राजस्व अभिलेख में गलत रूपेण दर्ज करवा दिया है, जिस उक्त वनाराम के खातेदारी हिस्से को जो वर्तमान जमाबंदियों में अप्रार्थीगण संख्या-1 से 7 के नाम दर्ज सुदा है को इस वाद-पत्र में सुविधा की दृष्टि से आगे "वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात" संबोधित किया गया है, जो इस वाद-पत्र की विषय वस्तुत है, जिस संबंध में ही प्रार्थिनी द्वारा यह वाद लाया गया है जिससे उक्त खसरान की आराजियात के दीगर सह खातेदार के खातेदारी हक हिस्सों के संबंध में प्रार्थिनी द्वारा इस वाद मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है, जिससे दीगर सह खातेदार इस वाद मे कानूनन आवश्यक पक्षकार नही होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है।

यह कि मृत वनाराम एवं उनके वारिसान पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू कानूनन से शासित होते है। प्रार्थिनी के पिता वनाराम की मृत्यु दिनांक: - 25/07/1982 को निर्वासियत हुई, जिनकी मृत्युपरान्त उक्त मृत वनारामजी के विधिक वारिसान इनके तीन पुत्र चेलाराम, दौलाराम व पुनाराम पुत्रगण स्व. वनाराम एवं पत्नि गोमीबाई एवं तीन पुत्रियां नेनू, पोनी, दाकू पुत्रियां स्व. वनाराम है, जिसमे से दौलाराम की मृत्यु होने पर मृत दौलाराम के विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या- 3 से लगाय- 7 है एवं गोमीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है, जिनके विधिक वारिसान प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण संख्या -1 से लगाय- 9 है। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकारीगण प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण संख्या -1 से लगाय -9 है।

यह कि उपरोक्तानुसार प्रार्थिनी के पिता मृत वनाराम की निर्वासियत मृत्यु होने पर उनके पीछे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारी प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण संख्या- 1 से लगाय-9 है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के अनुसार मृत वनाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण संख्या-1 से लगाय- 9 उपरोक्त खसरान की आराजियात में विद्यमान मृत वनाराम की खातेदारी हुए है यानि वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात जो वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदियों मे अप्रार्थीगण संख्या-1 से लगाय-9 के नाम ही दर्ज है, मे प्रार्थिनी एवं प्रतिवादी संख्या-8 व 9 का भी बतौर मृत वनाराम के विधिक वारिसान की हैसियत से समान रूपेण खातेदारी हक अधिकार कानूनन निर्दिष्ट है यानि मृत वनाराम के वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात में प्रार्थिनी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-3 से 7 का 1/6 हिस्सा,

पेज नम्बर 3 पर लगातार.....




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देगुरी (पाली)

पेज नम्बर 3 राजस्व विधि नम्बर 11/2018 अनवान दाकु बनाम वेलाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देरूरी...

प्रतिवादी संख्या-8 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या -9 का 1/6 हिस्सा पैतृक हक अधिकार आधिपत्य का संयुक्त खातेदारी का विद्यमान है, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थीगण संख्या -3 से 7 के पिता मृत वनाराम को भली-भांति होते हुए भी मृत वनाराम की मृत्युपरान्त बाला बाला सिर्फ इनके नाम से ही विरासत नामान्तरण के जरिये राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दिया है जबकि प्रार्थिनी एवं प्रतिवादी संख्या -8 व 9 का भी अप्रार्थीगण संख्या-1 से 7 साथ-साथ बतौर विधिक वारिसान के कानूनन हक अधिकार निहित है। प्रार्थिनी को राजस्व रिकार्ड बाबत जानकारी नहीं थी अभी कुछ रोज पूर्व वादग्रस्त आराजियात की जमाबंदिया राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर प्रार्थिनी को यह जानकारी हुई कि उपरोक्त खसरा न की आराजियात के मृत वनाराम के वादग्रस्त खातेदारी हिस्सा में सिर्फ अप्रार्थीगण संख्या -1 से 7 का ही नाम दर्ज है, जिस पर वादिनी द्वारा अप्रार्थीगण को पिता से विरासत से प्राप्त सुदा वादग्रस्त हिस्सा की आराजिया में प्रार्थिनी एवं प्रतिवादी संख्या-8 व 9 का नाम दर्ज कराने का अप्रार्थीगण को कहा, किन्तु आज कल बतला कर टालम-टोली कर रहे हैं एवं नाम दर्ज नहीं करवा रहे हैं एवं उल्टा वादग्रस्त हिस्सों की आराजियात को मात्र उनका ही गलत रूपेण नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की बदनियत से प्रार्थिनी के विधिक एवं जायज हक अधिकार एवं हिस्से सहित खुर्दबुर्द-फरोख्त, अन्यत्र हस्तान्तरण कर प्रार्थिनी को अपने विधिक हक अधिकारों से वंचित रखने पर आमादा है उपरोक्त रूपेण मृत वनाराम की विधिक वारिस उत्तराधिकारी की हैसियत से वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात में प्रार्थिनी अपने पैतृक हक अधिकारों अनुसार खातेदार घोषित कराने की कानूनन अधिकारी है अतः प्रार्थिनी यह वाद विरुद्ध अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात में वादिनी के पिता मृत वनाराम के वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण संख्या-1 से 7 के नाम दर्ज है, में प्रार्थिनी एवं प्रतिवादी संख्या-8 व 9 को भी मृत वनाराम की विधिक वारिसान उत्तराधिकारी के अप्रार्थीगण संख्या-1 से 7 के साथ समान रूपेण सह खातेदार घोषित कराने हेतु व नाम दर्ज कराने हेतु एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह वाद विरुद्ध अप्रार्थीगण हस्र धारा-88, 188, 92ए राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है, जो प्रार्थिनी का मूल वाद प्रथम दृष्टया कामयाब होने योग्य है, जिसमें प्रार्थिनी की सफलता के ठोस आधार एवं आसार एवं दस्तावेज प्रमाण हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिनी के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिनी के पक्ष में है एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थिया पर लागू होता है।

यह कि मूल वाद के निर्णय में लम्बा समय लगेगा, जिस दौरान मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाकर वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात, जो अप्रार्थीगण संख्या-1 से 7 के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज सुदा

विरुद्ध, जिसमें वादिनी का पैतृक हक हिस्सा विद्यमान है जो कि अप्रार्थीगण के नाम मात्र

पेज नम्बर 4 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) देरूरी (बाली)



अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 से 6 की ओर इकबालिया जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र के पैरा एक में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में हमारे पिता वनाराम पुत्र भागारामजी की खातेदारी आधिपत्य का हिस्सा विद्यमान था, जिसके स्वर्गवास पश्चात् मृत वनाराम के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण प्रार्थीनी सहित प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 एवं मृत दौलाराम के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या-3 से लगाय-7 एवं नेनू, पोनी पुत्रिया स्व. वनाराम का समान रूपेण पैतृक हक हिस्सा एवं आधिपत्य विद्यमान है। किन्तु भूल एवं मृत दौलाराम के नाम से ही दर्ज हुआ है, जो गलत है। वादग्रस्त आराजी भरे पिता स्व. वनारामजी की वारिसान पुत्रियों का भी समान है अधिकार एवं हिस्सा कानूनन विद्यमान है।

यह है कि हमारे ससूर/दादा मृत वानारामजी की निर्वसियत मृत्यु होने पर उनके पीछे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण प्रार्थीनी एवम् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 एवम् नेनू व पोनी पुत्रिया वनाराम का है, जो वादग्रस्त आराजियात में विद्यमान मृत वनाराम की खातेदारी हिस्से के समान रूपेण हकदार एवम् अधिकारी है यानि वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगाय 7 के नाम दर्ज है, उसमें प्रार्थिनी एवम् नेनू, पोनी पुत्रिया वनाराम का भी बतौर मृत वनाराम के विधिक वारिसान की हैसियत से समान रूपेण खातेदारी हक अधिकार कानूनन निहित है। मृत वनाराम के वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात में प्रार्थिनी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 से 7 का 1/6 हिस्सा, नेनू पुत्री वनाराम का 1/6 हिस्सा, एवम् पोनी पुत्री वनाराम का 1/6 हिस्सा पैतृक हक अधिकार अधिपत्य का सयुक्त रूपेण विद्यमान है, जिस अनुरूप खातेदारी घोषणा हेतु प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद प्रथम दृष्टया कामयाब होने योग्य है एवम् प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थिनी के पक्ष में है एवम् सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिनी के पक्ष में है एवम् अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। जिससे मूल वाद के निस्तारण के तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वकूलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न बिन्दुओ पर विचारण किया गया-

प्रथम दृष्टया मामला - वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में व्यक्त किया प्रार्थिनी के पिता वनाराम की मृत्यु दिनांक 25.07.1982 को निर्वसियत हुई। जिनके विधिक वारिसान प्रार्थीया

पेज नम्बर 8 पर लगातार....


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देवुती, पं.



पेज नम्बर 6 राजस्व विधि नम्बर 11/2018 अनवान दाकु बनाग घेलाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसुरी.

एवम् अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 7 तथा वनाराम की पुत्रीयों नेनू व पोनी का समान रूपेण खातेदारी हक अधिकार निहित है। अर्थात् मृत वनाराम के वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात में प्रार्थिनी का 1/6 हिस्सा विद्यमान है। जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को होते हुए भी विरासत नामान्तरकरण के जरिये राजस्व अभिलेख में सिर्फ इनके नाम दर्ज करवा दिये। जिससे अप्रार्थीगण इसका फायदा उठाने की बदनियत से प्रार्थिनी के विधिक एवम् जायज हक अधिकारो से वंचित रखने पर आमादा है। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक रोका जाना नितांत आवश्यक है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीयों द्वारा अपने वाद में कही भी मौके पर कब्जा काश्त दर्शाया नहीं है। तथा उक्त वाद प्रार्थीयों ने घोषणा का पेश किया है जबकि प्रार्थीयों को म्यूटेशन अपील करनी थी। अतः प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है।

न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य अधिकार अभिलेख जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त आराजियात व इकबालिया जबाव से प्रथम दृष्टया से यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में स्व वनाराम की मृत्यु के पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई है। जबकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रार्थीयों भी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान के तौर पर स्व. वनाराम की खातेदारी में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयों के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का सन्तुलन :- अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा सन्तुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयों के पक्ष में साबित होने व राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीयों का नाम दर्ज नहीं होने से उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द या अन्य हस्तान्तरण से प्रार्थीयों को ज्यादा असुविधा होगी। जिससे सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीयों के पक्ष में साबित होता है।

अपूरणीय क्षति -अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थीयों ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज का अप्रार्थीगण फायदा उठाकर खुर्दबुर्द करने व हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीयों को अपूर्णनीय क्षति होगी एवम् प्रार्थी के हक अधिकारो पर भारी कुठारगात होगा। इस संबंध में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के नाम से वादग्रस्त आराजी बतौर खातेदार दर्ज है जिससे प्रार्थीयों का कोई विधिक हक अधिकार नहीं है। मौके पर अप्रार्थीगण की फसल बोई हुई है। इसलिए अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त और खातेदारी की आराजी को लेकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

पेज नम्बर 7 पर लगातार.....



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसुरी (भाली)

पेज नम्बर 7 राजस्व विधि नम्बर 11/2018 अगवान वाकु बनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी

अपूर्णनीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी स्व बनाराम जी से प्राप्त होना बताया है। बनाराम जी के वारिस अप्रार्थीगण के अलावा पुत्रिया नेनू, पोनी, दाकू हुए जिस अनुरूप वादग्रस्त आराजी में प्रार्थियों का 1/6 हिस्सा होना प्रतीत होता है। जिसके खण्डन में अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया है। जिससे उपरोक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थीगण का पैतृक हक अधिकार स्व बनाराम जी के वारिस के रूप में वादग्रस्त आराजी में सिर्फ 1/6-1/6 बनना प्रथम दृष्टया आंशिक रूप से साबित होता है जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी के अनुसार 1/3-1/3 दर्ज है। हालांकि खातेदारी हक अधिकारों के संबंध में साक्ष्य आदि से मूल वाद के गुणावगुण पर निर्णय होगा। जिससे अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात में जब तक हिस्से तय नहीं हो जावे, जब तक कानूनन किसी भी सह खातेदार को अपनी मन मर्जी से एवं जमाबन्दी में मात्र गलत हिस्सा दर्ज हो जाने से वादग्रस्त आराजियात में से किसी हिस्से या को अन्यत्र हस्तान्तरित करने का कानूनन हक अधिकार नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन में दौराने वाद वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द आगे हस्तान्तरण किये जाने की सूरत में प्रार्थियों को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होता है। अतः अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थियों के पक्ष में साबित होता है।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दुओं प्रार्थियों के पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

आदेश

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थियों का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि- अप्रार्थी वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद गांव-नारलाई, पटवार क्षेत्र- नारलाई, तहसील-देसूरी, जिला-पाली (राज.) में संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजियात खसरा नम्बर 2325, 2326, 2328, 2329, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2366 कुल खसरा- 22 कुल क्षेत्रफल - 59.3800 हैक्टर, कुल लगान रूपयां- 1133.38 एवं खसरा नम्बर- 1449, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, कुल खसरा-14 कुल क्षेत्रफल-11.8100 हैक्टर, कुल लगान रूपयां - 284.172 में वर्तमान राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज है, को.....

पेज नम्बर 8 पर लगातार.....




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज नम्बर 8 राजस्व विविध नम्बर 11/2018 अनवान दाकु बनाम घेलाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी...

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 किसी प्रकार से खुर्दबुर्द अन्यत्र हस्तान्तरण नही करे एवम् प्रार्थीनी के पैतृक हक हिस्सा की आराजी में प्रार्थिया के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फ़ैसल भुगमार होकर नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद के साथ नत्थी हो।



(राजलक्ष्मी गहलोत)

सहायक कलेक्टर

(एस.डी.ओ.) देसूरी

निर्णय/आदेश आज दिनांक- 31/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)